



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2009/माघ 24, 1930

No. 62]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2009

विषय : चीन जन गण एवं यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 'कतिपय फास्फोरस आधारित रासायनिक यौगिकों' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 14/3/2009-डीजीएडी.—जबकि एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम केमिकल मैनुफैक्चरर्स ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है कि जिसमें चीन जन गण (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कतिपय फास्फोरस आधारित रासायनिक यौगिकों, नामतः पी सी एल 3, पी सी एल 5, टी एम पी तथा टी पी पी आई (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) और चीन जन गण एवं यूरोपीय संघ (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पी ओ सी एल 3 (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश (देशों) से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को "क्षति" और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं और इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार विचाराधीन उत्पादों के कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" की जांच प्रारंभ करते हैं ।

3. घरेलू उद्योग

यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम के केमिकल मैनुफैक्चरर्स (ए एस एम ई सी एच ई एम), मुंबई ने प्रस्तुत किया है। मेसर्स यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड ने क्षति से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है, जबकि मेसर्स पंजाब केमिकल्स एण्ड क्रॉप प्रोटेक्शन लि०, मे० संध्या इण्डस्ट्रियल केमिकल्स, मे० संध्या डाइज एण्ड केमिकल्स, मे० एस एम केमिकल्स, मे० एक्सेल इण्डस्ट्रीज लि०, मे० केमीनोवा इण्डिया लि० एवं मे० फार्मा केमिकल्स इण्डस्ट्रीज ने आवेदन का समर्थन किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड एवं सहयोगियों का भारतीय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। अतः यह आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) तथा नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड को उपर्युक्त नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है।

4. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद "कतिपय फॉस्फोरस आधारित रासायनिक यौगिक" है अर्थात्

- (1) फॉस्फोरस ट्राइ क्लोराइड (पी सी एल 3)
- (2) फॉस्फोरस पेन्टा क्लोराइड (पी सी एल 5)
- (3) फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड (पी ओ सी एल 3)
- (4) ट्राइफिनाइल फॉस्फाइट (टी पी पी आई)
- (5) ट्राइमिथाइल फॉस्फाइट (टी एम पी)

आवेदक ने कहा है कि इन उत्पादों के समानार्थी शब्द निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं:-

उत्पाद का नाम	समानार्थी नाम
फॉस्फोरस ट्राइ क्लोराइड (पी सी एल 3)	फॉस्फोरस (III) क्लोराइड, फॉस्फोरस क्लोराइड
फॉस्फोरस पेन्टा क्लोराइड (पी सी एल 5)	फॉस्फोरस क्लोराइड
फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड (पी ओ सी एल 3)	फॉस्फोरस (V) क्लोराइड
ट्राइफिनाइल फॉस्फाइट (टी पी पी आई)	फॉस्फोरस एसिड ट्राइफिनाइल ईस्टर, टी पी पी
ट्राइमिथाइल फॉस्फाइट (टी एम पी)	फॉस्फोरस एसिड ट्राइमिथाइल ईस्टर, फॉस्फोनिक एसिड ट्राइमिथाइल ईस्टर, मिथाइल फॉस्फाइट

प्रत्येक संबद्ध वस्तु का सीमाशुल्क वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

संबद्ध उत्पाद	सीमाशुल्क वर्गीकरण
(पी सी एल 3)	28121021
(पी सी एल 5)	28121022
(पी ओ सी एल 3)	28121030
(टी पी पी आई)	29209041
(टी एम पी)	29209099

सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न रोगाणुनाशकों, कीटनाशकों एवं भेषजों के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है।

5. समान वस्तु

आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबद्ध वस्तुएं नियम 2 (घ) के तहत 'समान वस्तु' की परिभाषा के संदर्भ में संबद्ध देश (देशों) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है। यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबद्ध वस्तु एवं संबद्ध देश (देशों) से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबद्ध वस्तु को उपर्युक्त नियम के अर्थों के भीतर संबद्ध देश (देशों) से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं माना जाएगा।

6. शामिल देश

पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (घ) के संदर्भ में वर्तमान जांच में शामिल देश फॉस्फोरस आधारित रासायनिक यौगिकों अर्थात् पी सी एल 3, पी सी एल 5, टी एम पी एवं टी पी पी आई हेतु चीन जन गण एवं पी ओ सी एल 3 हेतु चीन जन गण एवं यूरोपीय संघ हैं।

7. सामान्य मूल्य

आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और इसलिए चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम के अनुबंध - 1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने निवेदन किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश संबंधी सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है अतः चीन जन गण में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भारत को एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जो बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों एवं समुचित लाभ मार्जिन को शामिल करते हुए विधिवत समायोजित है।

इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान पीले फॉस्फोरस की कीमत में उल्लेखनीय परिवर्तन को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने निर्यात के समय पर जिस माह में संबद्ध उत्पाद का आयात किया गया था, उस माह में पीले फॉस्फोरस की कीमत पर विचार किया है। यह तर्क दिया गया है कि यदि लगभग एक महीने के विलंब को देखा जाए तो भी निष्कर्ष समान रहेगा।

यूरोपीय संघ के संबंध में, ई यू की बिक्री कीमत को सामान्य मूल्य माना गया है। ई यू में इस बिक्री कीमत का निर्धारण ई यू में आयातक/उपभोक्ता द्वारा उत्पाद के आयात की कीमत के आधार पर किया गया है। वैकल्पिक रूप से ई यू में सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों एवं समुचित लाभ मार्जिन को शामिल करते हुए विधिवत समायोजित अनुमानित उत्पादन लागत पर विचार करके परिकलित मूल्य के आधार पर किया गया है।

नियम के संदर्भ में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

8. निर्यात कीमत

आवेदक ने आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत कीमत का निर्धारण करने के लिए अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन एवं पत्तन व्ययों के आधार पर समायोजनों का दावा किया गया है। प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद हेतु अलग-अलग निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। प्रस्तावों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के आवेदक के दावे पर प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ विश्वास नहीं किया गया है।

जांच प्रारंभ करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

9. पाटन मार्जिन

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि संबद्ध देश (देशों) में प्रत्येक संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उनकी निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश (देशों) के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। आवेदक ने दावा किया है कि जांच अवधि के भीतर मुख्य निविष्टियों की कीमत में उल्लेखनीय परिवर्तन के मद्देनजर निर्यात के समय पर प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत हेतु संबद्ध उत्पाद में आयात के महीने के दौरान की कीमत पर विचार किया जा सकता है। आवेदक ने निर्यात के समय पर पीली फॉस्फोरस की कीमत का निर्धारण उसी माह की उत्पाद कीमत और कच्ची सामग्री की कीमत के अनुसार किया है। तथापि, आवेदक ने एक माह के समय विलम्ब हेतु अतिरिक्त पाटन मार्जिन का परिकलन किया है। यदि एक माह के समय विलम्ब पर विचार किया भी जाता है तो पाटन मार्जिन काफी अधिक बना रहता है।

इस चरण में पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रस्तावों के आधार पर निर्यात कीमत के निर्धारण के आवेदक के दावे पर विश्वास नहीं किया जा रहा है।

10. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

आवेदक ने नियमों के अनुबंध II के पैरा (iv) के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों पर सूचना प्रस्तुत की है। सूचना के आकलन से यह प्रदर्शित होता है कि:

(क) पी सी एल 5 के मामले में आयातों में सापेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। आयातों से बाजार में कीमत अवमूल्यन हो रहा है। जहाँ तक घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव का संबंध है, क्षति अवधि में घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को हो रहा वित्तीय घाटा जारी रहा। हालांकि क्षति अवधि में घाटे में कमी आई। लगाई गई पूंजी पर आय नगण्य थी और नकद लाभ प्रतिकूल बने रहे थे।

(ख) पी सी एल 3 के मामले में जब संगत अवधि के दौरान कुछ वस्तुओं को सीमाशुल्क स्वीकृति प्रदान की जा रही थी, तब काफी कम कीमतों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु कई प्रस्ताव भी किए जा रहे थे। प्रस्तावित कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से बहुत कम थीं। आयातों से बाजार में कीमत अवमूल्यन हो रहा है। जहाँ तक घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव का संबंध है, क्षति अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई, आयात हेतु प्रस्तावों की मौजूदगी के कारण जाँच अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, चीन की सामग्री के प्रस्तावों के कारण घरेलू

उद्योग जून, 2008 के बाद अपनी कीमतों को काफी कम करने के लिए बाध्य हुआ। जून और दिसम्बर, 2008 के बीच कीमतों में लगभग 55 प्रतिशत की गिरावट आई [लगभग 197 रूपए प्रति किग्रा. से घटकर लगभग 89 रूपए प्रति किग्रा.]। यद्यपि घरेलू उद्योग जाँच अवधि से पूर्व की अवधि में आयातों की गैर-मौजूदगी में अपने निष्पादन में सुधार और लाभ प्राप्त कर पाया था परन्तु उसके बाद आयातों की उपस्थिति से उसमें गिरावट आई। लाभप्रदता जिसमें जून, 2008 तक सुधार हो रहा था, उसमें उसके बाद गिरावट आनी शुरू हो गई। लागत समायोजित कीमतों में क्षति अवधि में अत्यधिक कमी प्रदर्शित होती है जो चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जा रहे आपूर्ति हेतु प्रस्तावों के कारण प्रतीत होती है।

(ग) पी ओ सी एल 3 के मामले में जांच अवधि में संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन की सूचना मिली थी जिसकी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम थीं। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। आयातों से बाजार में कीमत अवमूल्यन हो रहा है। जहाँ तक घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव का संबंध है, यद्यपि क्षति अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई परन्तु क्षमता उपयोग में गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा था जिसमें क्षति अवधि में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 2008 के बाद घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतों में अत्यधिक कमी किए जाने के बावजूद जाँच अवधि के भीतर बिक्री मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई। परिणामस्वरूप लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में भी कमी हुई।

(घ) टी पी पी आई के मामले में जब संगत अवधि के दौरान कुछ वस्तुओं को सीमाशुल्क स्वीकृति प्रदान की जा रही थी, तब काफी कम कीमतों पर सामग्री की आपूर्ति हेतु कई प्रस्ताव भी किए जा रहे थे। प्रस्तावित कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से बहुत कम थीं। आयातों से बाजार में कीमत अवमूल्यन हो रहा है। जहाँ तक घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव का संबंध है, क्षति अवधि में घरेलू बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा होना जारी रहा और क्षति अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई। लगाई गई पूंजी पर आय नगण्य थी जबकि नकद लाभ प्रतिकूल बने रहे। इसके अतिरिक्त, जुलाई, 2008 के बाद घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतों में अत्यधिक कमी किए जाने के बावजूद जाँच अवधि के भीतर बिक्री मात्रा में अत्यधिक गिरावट आई।

(ङ.) टी एम पी के मामले में जांच अवधि में संबद्ध देशों से अत्यधिक पाटन की सूचना मिली थी जिसकी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम थीं। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। आयातों से बाजार में कीमत अवमूल्यन हो रहा है। जहाँ तक घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव का संबंध है, क्षति अवधि में घरेलू बिक्री में गिरावट आई। यद्यपि उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में मामूली सुधार हुआ था, तथापि वस्तु सूची में वृद्धि हुई है।

क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता तथा परिणामस्वरूप नियोजित पूँजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा जुलाई, 2008 के बाद कीमतों में अत्यधिक कटौती किए जाने के बाद भी जाँच अवधि के भीतर बिक्री की मात्रा में अत्यधिक कमी लक्षित की गई।

- (च) यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है। घरेलू तथा आयातित उत्पादों के बीच कीमत में अत्यधिक अंतर है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को जून/जुलाई, 2008 में/के बाद कीमतों में अत्यधिक कटौती करने पर बाध्य होना पड़ा जबकि पीले फॉस्फोरस की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि हो रही थी।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि संबद्ध देश (देशों) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को “क्षति” हुई है जो जाँच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करते हैं।

11. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से 31 दिसंबर, 2008 है। तथापि क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2005- मार्च, 2006; अप्रैल, 2006-मार्च, 2007; अप्रैल, 2007-मार्च, 2008 और जांच अवधि (पीओआई) को शामिल किया जाएगा। क्षति के खतरे के लिए जांच अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी।

12. भूतलक्षी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाना

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है कि पाटन काफी पहले से हो रहा है, निर्यातकों को इस बात की पूरी जानकारी है कि उनके द्वारा पाटन किया जा रहा है; आयातकों को निर्यातकों द्वारा पाटन किए जाने की पूरी जानकारी है या होनी चाहिए थी; घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत में अत्यधिक अंतर है जिसमें भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस संबंध में आवेदक के दावे पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं और संबद्ध पक्षों को इस संबंध में अपने विचार सामने रखने हेतु आमंत्रित करते हैं।

13. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश (देशों) के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास/यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल के कार्यालय के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रारूप तथा निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से पत्र भेजा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार भी निम्नलिखित को लिख सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

14. समय सीमा

इस जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना का नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगोपनीय रूपांतरण अथवा गोपनीय सूचना के अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना सार्थक हो। यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश बनाना संभव न हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त पैरा में किए गए उल्लेख के होते हुए भी यदि प्राधिकारी यह समझते हैं कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा ऐसी सूचना को सामान्यीकृत या सारांश के रूप में प्रकट करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

16. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

17. असहयोग

ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2009

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of 'Certain Phosphorous based chemical compounds' originating in or exported from China PR & European Union.

No. 14/3/2009-DGAD.—The Association of Small & Medium Chemical Manufacturers (ASMECHEM), Mumbai has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) alleging dumping of 'Certain Phosphorous based chemical compounds' namely PCL3, PCL5, TMP and TPPI (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country) and POCL3 (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and European Union (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of anti dumping investigation for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of subject goods from the subject country(ies), 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist to justify initiation of an investigation in terms of the Rules; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping of the products under consideration, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

3. Domestic Industry

The Application has been filed by Association of Small & Medium Chemical Manufacturers (ASMECHEM), Mumbai on behalf of the domestic industry. M/s. United Phosphorus Limited has provided injury information, whereas M/s. Punjab

61067/09-3

Chemicals and Crop Protection Ltd, M/s. Sandhya Industrial Chemicals, M/s. Sandhya Dyes & Chemicals, M/s. S.M. Chemicals, M/s. Excel Industries Limited, M/s. Cheminova India Ltd and M/s. Pharma Chemicals Industries have supported the application. As per the evidence available on record, production of United Phosphorus Limited accounts for a major proportion of the total domestic production and production of United Phosphorus Limited along-with supporters is more than 50% of Indian production. The application thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules. Further, United Phosphorus Limited is being treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) supra.

4. Products under consideration

The products under consideration are 'Certain Phosphorous based chemical compounds', viz:

- (1) Phosphorous trichloride (PCL₃)
- (2) Phosphorous pentachloride (PCL₅)
- (3) Phosphorous oxychloride (POCL₃)
- (4) Triphenyl phosphite (TPPI)
- (5) Trimethyl phosphite (TMP)

The applicant states that these products have the following synonyms as tabulated:

Product name	Synonym name
Phosphorus Trichloride (Pcl ₃)	Phosphorus(III) chloride, Phosphorus Chloride
Phosphorus Oxychloride (Pocl ₃)	Phosphoryl chloride
Phosphorus Pentachloride (Pcl ₅)	Phosphorus(V) chloride
Triphenyl Phosphite (TPPI)	Phosphorus acid triphenyl ester, TPP
Trimethyl Phosphite (TMP)	Phosphorus acid trimethyl ester, Phosphonic acid trimethyl ester, Methyl Phosphite

PCL₅, POCL₃ and PCL₃ are inorganic chemicals, classifiable under Chapter 28, whereas, TMP and TPPI are organic chemicals, classifiable under Chapter 29.

Customs classification of each of the subject goods is as follows:

Subject Product	Customs Classification
PCL3	28121021
PCL5	28121022
POCL ₃	28121030
TMP	29209041
Other (TPPI)	29209099

The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Products under consideration are extensively used in production of various pesticides, insecticides and pharmaceuticals.

5. Like Articles

The Applicant has claimed that the each of the subject goods produced by the domestic industry are like article to the respective subject goods originating in or exported from the subject country(ies) in terms of the definition of 'like article' under Rule 2 (d). It has been stated that there is no significant difference in each of the subject goods produced by the applicant and the respective subject goods exported from the subject country (ies). The applicant claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, each of the subject goods produced by the domestic industry are being treated as like articles of the respective subject goods imported from the subject country(ies) within the meaning of the Rules supra.

6. Country(ies) involved

In terms of Rule 2(f) of the AD Rules, the country(ies) involved in the present investigation are China PR for **Phosphorous based chemical compounds'** namely PCL3, PCL5, TMP and TPPI and China PR & European Union for POCL3.

7. Normal value

The applicant has claimed that China PR should be treated as Non Market Economy and therefore Normal value in case of China PR should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annex-I of the Rules. The applicant has submitted that India can be considered as an appropriate market economy third country for determination of normal value in China PR, pleading that information for market economy third country is not available to them. The Normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India, duly adjusted, to include selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin.

Further, in view of significant change in the price of yellow phosphorus within the period of investigation, the applicant has considered price of yellow phosphorus at the time of exports, considering the month in which the subject product was imported. It has been contended that even if a time lag of one month or so is considered, the conclusion will be the same.

In respect of European Union, selling price in EU has been considered as Normal value. This selling price in EU has been determined based on the price at which an importer/ consumer in EU has imported the product. Alternatively, Normal value in EU has been determined on the basis of constructed value, considering estimates of cost of production, duly adjusted, to include selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin.

There is sufficient evidence with regard to Normal Value to justify initiation of an anti dumping investigation in terms of the rules.

8. Export Price

The applicant has claimed export price based on the transaction wise data provided by IBIS. Adjustments have been claimed on account of inland freight, ocean freight, marine insurance, commission and port expenses to arrive at net export price at ex-factory level. Export price has been determined separately for each of the products under consideration. The applicant's claim to determine the export price on the basis of offers is not being relied upon for the purposes of the initiation.

There is sufficient evidence with regard to export price to justify initiation of an investigation.

9. Dumping margin

There is sufficient evidence that the Normal value of each of the subject goods in the subject country(ies) is significantly higher than their net export price, prima-facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country(ies). The applicant has claimed that in view of significant change in the prices of major input within the period of investigation, the price of the major raw material at the time of export, considering the month in which the subject product was imported may be considered. The applicant has considered price of yellow phosphorous at the time of exports by considering the same month for product price and raw material price. However, the applicant has additionally computed the dumping margin by considering one-month time lag. Even if a time lag of one month or so is considered, the dumping margins remain significant.

The applicant's claim to determine the export price on the basis of offers is not being relied upon for the purposes of determining the Dumping margin at this stage.

10. Injury and Causal Link

The applicant has furnished information on various parameters relating to injury to the domestic industry as prescribed under para (iv) of Annexure – II of the Rules. The evaluation of the information shows that:

- (a) In case of PCL5, imports have increased significantly in absolute terms and in relation to production & consumption in India. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Imports are suppressing the prices in the market. As regards consequent impact of imports on the domestic industry, domestic sales, production, capacity utilization deteriorated over the injury period. The domestic industry continued to suffer financial losses (even though the losses reduced over the injury period). Return on capital employed was negligible and cash profit continued to remain adverse.
- (b) In case of PCL3, even when some goods have been customs cleared during the relevant period, a number of offers for supply of material at significantly low prices were also being made. The prices being offered were materially lower than the selling prices of the domestic industry. Imports are suppressing the prices in the market. As regards consequent impact of imports on the domestic industry; production and capacity utilization declined over the injury period, the domestic sales declined within the investigation period because of presence of offers for imports. Further, the domestic industry was forced to reduce the prices substantially after June, 2008 because of offers for Chinese material. The prices declined by about 55% between June and Dec., 2008 [from over Rs. 197 per kg. to about Rs. 89 per kg]. Though, the domestic industry was able to improve its performance and earn profits in the absence of imports in the period prior to the POI but the same deteriorated in presence of imports thereafter. Profitability, which was improving till June, 2008, also started declining thereafter. The cost adjusted prices saw significant erosion over the injury period, which appears to

be on account of offers for supplies being made by the Chinese suppliers.

- (c) In case of **POCL3**, significant imports were reported from subject countries in the POI, prices of which were materially lower than the prices offered by the domestic industry. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Imports are suppressing the prices in the market. As regards consequent impact of imports on the domestic industry, though production increased but capacity utilization declined over the injury period. However, the domestic industry was suffering financial losses, which increased over the injury period. Further, sales volumes declined significantly within the investigation period even when the domestic industry reduced prices significantly after July, 2008. Consequently, the return on capital employed and cash profits also deteriorated.
- (d) In case of **TPPI**, some material has been customs cleared during the relevant period; however, a number of offers for supply of material at significantly low prices were also being made. The prices being offered were materially lower than the selling prices of the domestic industry. Imports are suppressing the prices in the market. As regards consequent impact of imports on the domestic industry, domestic sales, production, capacity utilization deteriorated over the injury period. The domestic industry continued to suffer financial losses, which increased during the injury period. Return on capital employed was negligible, whereas cash flow continued to remain adverse. Further, sales volumes declined significantly within the investigation period even when the domestic industry reduced prices significantly after July, 2008.
- (e) In case of **TMP**, significant imports were reported in the POI, prices of which were materially lower than the prices offered by the domestic industry. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Imports are suppressing the prices in the market. As regards consequent impact of imports on the domestic industry, domestic sales, deteriorated over the injury period. Though there were marginal improvement in production and capacity utilization but the inventory has increased.

Profitability and consequently return on capital employed and cash profits deteriorated over the injury period. Further, sales volumes declined significantly within the investigation period even when the domestic industry reduced prices significantly after July, 2008.

- (f) It has been contended that the domestic industry is threatened with material injury in respect of each of the products under consideration. The price differences between the domestic and imported products are too significantly high. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce the prices substantially in/after June/July, 2008, even when the costs were going up due to global increase in the prices of yellow phosphorus.

There is sufficient evidence that the 'injury' to the domestic industry has been caused by dumped imports of the subject goods from the subject country (ies) to justify initiation of an investigation.

11. Period of investigation

The period of investigation for the purpose of present investigation is **1st October 2007 to 31st December 2008**. However, the injury investigation period will cover the periods April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, April 2007-March 2008 and the Period of Investigation (POI). For threat of injury, the data beyond the POI would also be examined.

12. Imposition of anti dumping duties on Retrospective basis

The applicant has requested for retrospective imposition of duty on the grounds that there is history of dumping, the exporters are well aware that they are resorting to dumping; importers are, or should have been, well aware that the exporters are practicing dumping; there is significant price difference between the domestic and imported products, which is likely to increase further in future. On the basis of information submitted, the Authority proposes to consider the claim of the applicant in this regard and invites the interested parties to make their submissions in this regard as well.

13. Submission of information

The exporters in the subject country(ies) and their Governments through their Embassy/ Office of the Delegation of European Union in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and

610 GI/09-5

manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

As per Rule 6(5) of Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the articles under investigation, and to representative consumer organizations that can furnish information, which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below.

14. Time-limit

Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

15. Submission of Information on Non-Confidential basis

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

16. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

17. Non-cooperation

In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority